DAILY CURRENT AFFAIRS

Result Mitra

10 April 2025

THE HINDU

The Indian EXPRESS

Hindustan Times

दैनिक जागरण

जनसत्ता

UPSC(IAS/PCS) AND ALL COMPITETIVE EXAM

pib

THE HINDU

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

ABHAY SIR

Topic 1:- भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली माल ट्रांसफर सुविधा रोकी, व्यापार पर असर पड़ेगा

Topic 2:- तिरुपति-कटपडी रेलवे लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट

Topic 3:- राज्यपाल और अनुच्छेद 200: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

Topic 4:- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) का विलय – चौथा चरण

Topic 5 - कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) लिमिटेड

भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली माल ट्रांसफर सुविधा रोकी, व्यापार पर असर पड़ेगा

Result Mitra

बांग्लादेश को भारी नुकसान, एक्सपोर्ट लागत बढ़ेगी: भारत ने रद्द की ट्रांस-शिपमेंट सुविधा, बांग्लादेशी अंतरिम PM के चीन में दिए विवादित बयान का असर

नई दिल्ली | 1 घंटे पहले

सोर्स :– भास्कर न्यूज

- भारत ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांस-शिपमेंट सुविधा (Trans-shipment Facility) को बंद कर दिया है।
- इस फैसले की जानकारी 8 अप्रैल को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक सर्कुलर जारी कर दी।

क्या थी ये सुविधा?

- 2020 से चली आ रही इस व्यवस्था के तहत बांग्लादेश को अनुमति थी कि वह भारत के बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स के जरिए अपना एक्सपोर्ट कार्गो तीसरे देशों में भेज सके। इससे बांग्लादेश को समय और लागत दोनों में राहत मिलती थी।

Result Mitra

अब क्यों रोकी गई ये सुविधा?

- हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने चीन के दौरे पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को "लैंडलॉक्ड" बताया था, यानी चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ और समुद्र तक कोई रास्ता नहीं।
- उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश ही बंगाल की खाड़ी का "गार्डियन" है। इस बयान के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया, और भारत ने यह सुविधा वापस ले ली।

इसका असर क्या होगा?

- ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के इस कदम से बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान होगा:
- उन्हें अब एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा खर्च और समय लगेगा।
- नेपाल, भूटान और अन्य देशों में माल भेजना मुश्किल होगा।
- बांग्लादेशी ट्रकों की वजह से भारत के कार्गो टर्मिनलों पर लगने वाला जाम भी कम होगा।

भारत को क्या फायदा?

- भारतीय एयरपोर्ट्स पर अब घरेलू एक्सपोर्टर्स को ज्यादा जगह मिलेगी।
- माल भेजने की प्रक्रिया तेज होगी।
- लागत भी कम हो सकती है।

भारत-बांग्लादेश व्यापार आंकड़े (2023-24 के अनुसार):

- **कुल द्विपक्षीय व्यापार:** लगभग 1,80,000 करोड़ रुपये (22 अरब डॉलर)
- **भारत से बांग्लादेश को निर्यात:** 16 अरब डॉलर

- **बांग्लादेश से भारत को आयात:** 6 अरब डॉलर
- भारत, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है (चीन के बाद)।
- भारत, बांग्लादेश को सबसे ज्यादा दवाइयाँ, वस्त्र, मशीनरी और पेट्रोलियम उत्पाद भेजता है।

भारत-बांग्लादेश ट्रांस-शिपमेंट सुविधा विवाद: शॉर्ट नोट्स

1. ट्रांस-शिपमेंट सुविधा क्या थी?

- बांग्लादेश को 2020 से भारत के बंदरगाहों/एयरपोर्ट्स से तीसरे देशों में माल भेजने की अनुमति थी।
- इससे लागत और समय दोनों की बचत होती थी।

2. भारत ने यह सुविधा क्यों रोकी?

- बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री यूनुस ने चीन में भारत के नॉर्थ-ईस्ट राज्यों को "लैंडलॉक्ड" बताया।
- कहा कि बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी का "गेटवे" और "गार्डियन" है।
- भारत ने इसे आपत्तिजनक मानते हुए सुविधा रोक दी।

3. बांग्लादेश पर असर:

- एक्सपोर्ट की लागत बढ़ेगी।
- समय और प्रक्रिया में देरी होगी।
- नेपाल-भूटान जैसे देशों को सामान भेजना कठिन होगा।

4. भारत को क्या फायदा:

- एयरपोर्ट्स और कार्गो टर्मिनल्स पर भीड़ घटेगी।
- भारतीय एक्सपोर्टर्स को ज्यादा जगह और कम लागत का लाभ मिलेगा।

5. व्यापारिक आंकड़े (2023-24):

- द्विपक्षीय व्यापार: 22 अरब डॉलर
- भारत का निर्यात: 16 अरब डॉलर
- आयात: 6 अरब डॉलर
- भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

6. वर्तमान संदर्भ:

- अमेरिका का 'रेसिप्रोकल टैरिफ' भी इसी समय लागू हुआ है।
- इस फैसले से क्षेत्रीय व्यापार और कूटनीतिक संबंधों पर असर पड़ेगा।

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. भारत ने बांग्लादेश को अपने क्षेत्र से होकर माल पारगमन (transit) की सुविधा दी है ताकि बांग्लादेश नेपाल और भूटान तक अपना व्यापार कर सके।
- 2. यह सुविधा केवल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के लिए दी गई है, न कि किसी तीसरे देश के लिए।
- 3. इस सुविधा के तहत भारत को कोई शुल्क नहीं मिलता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 2
- (d) 1 और 3

व्याख्या:

- कथन 1 सही भारत ने बांग्लादेश को अपने क्षेत्र से होकर नेपाल और भूटान तक माल पारगमन (transit) की सुविधा दी है, जिससे वह इन देशों के साथ व्यापार कर सके। इसे sub-regional connectivity बढ़ाने का एक हिस्सा माना जाता है।
- कथन 2: गलत - यह सुविधा केवल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने तक सीमित नहीं है; बल्कि इसमें बांग्लादेश को नेपाल और भूटान तक अपने ट्रकों के ज़रिए माल पहुँचाने की अनुमति भी शामिल है।
- कथन 3: गलत - भारत को इस पारगमन सुविधा के लिए शुल्क और उपयोग शुल्क (user fee) मिलता है, जो सीमा शुल्क के तहत लिया जाता है।

तिरुपति-कटपडी रेलवे लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट:

कैबिनेट का फैसला:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तिरुपति (आंध्र प्रदेश) से कटपडी (तमिलनाडु) तक की 104 किलोमीटर लंबी सिंगल रेलवे लाइन को डबल लाइन में बदलने की मंजूरी दे दी है।

कुल लागत:

- लगभग 1332 करोड़ रुपये
- परियोजना को रेलवे मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

प्रमुख लाभ:

- तीर्थ स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी:
- तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर (तिरुपति)
- श्रीकालहस्ती शिव मंदिर
- कनिपक्कम विनायक मंदिर
- चंद्रगिरी किला

- 400 से अधिक गांवों को जोड़ा जाएगा।
- लगभग 14 लाख लोगों को सीधे रेल सुविधा का लाभ मिलेगा।
- मौजूदा रेल नेटवर्क में 113 किलोमीटर की वृद्धि।

परियोजना की आवश्यकता क्यों:

- वर्तमान में यह मार्ग सिंगल लाइन है जिससे ट्रेनों की संख्या सीमित है।
- तीर्थ यात्रियों और लोकल यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
- डबल लाइन से ट्रेनों की गति, आवृत्ति और समय की बचत होगी।

रेलवे से संबंधित *UPSC Important Facts (Prelims + Mains* के लिए उपयोगी):

1. भारतीय रेलवे की शुरुआत:

- वर्ष 1853 में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली।
- दूरी: 34 किमी

2. रेलवे जोन की संख्या:

- वर्तमान में भारत में 18 रेलवे ज़ोन हैं।
- सबसे नया ज़ोन: दक्षिण कोस्ट रेलवे (South Coast Railway) – 2019 में बनाया गया (मुख्यालय: विशाखापत्तनम)

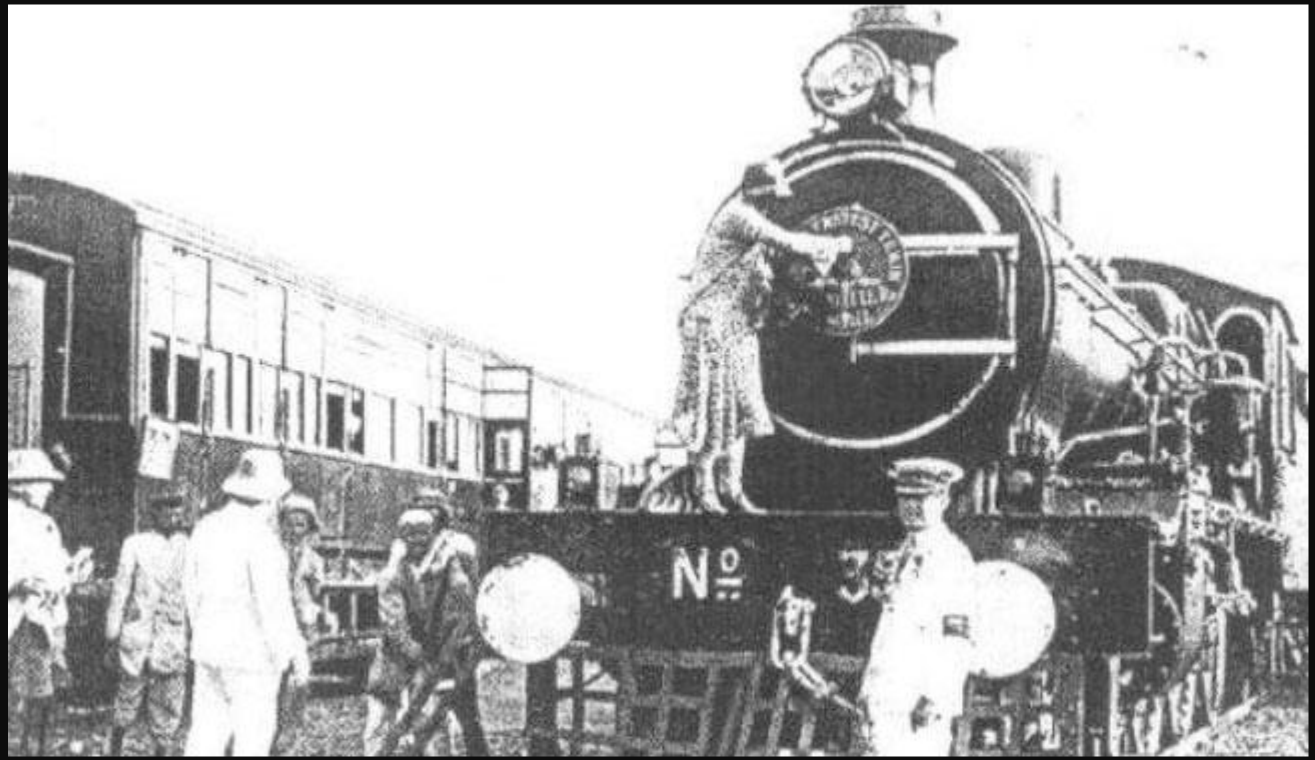

3. दुनिया में रेलवे नेटवर्क:

- भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है।
- चीन, अमेरिका और रूस के बाद।

4. रेलवे मंत्रालय की योजना:

- 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2030 तक।
- नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 तक।

5. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC):

- मालगाड़ियों के लिए विशेष रूट।

दो प्रमुख कॉरिडोर:

- पश्चिमी DFC: दादरी (UP) से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (मुंबई)
- पूर्वी DFC: लुधियाना से दनकुनी (पश्चिम बंगाल)

6. ट्रेन 18 / वंदे भारत एक्सप्रेस:

- भारत में निर्मित सेमी-हाई स्पीड ट्रेन।
- 160 किमी/घंटा तक की रफ्तार।

7. रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज:

- चिनाब ब्रिज (जम्मू-कश्मीर):
- दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज।
- ऊंचाई: 359 मीटर (एफिल टॉवर से भी ऊंचा)

8. रेल बजट:

- 2017 से रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जा रहा है।
- इससे पहले रेल बजट अलग से आता था।

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. भारत में रेल मंत्रालय, भारतीय रेलवे के संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।
- 2. Dedicated Freight Corridors' (DFC) का उद्देश्य माल ढुलाई को यात्री ट्रेनों से अलग करना है ताकि माल ढुलाई की दक्षता बढ़ाई जा सके।
- 3. भारत में पहली हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर पर कार्यान्वित की जा रही है।

उपयुक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

व्याख्या:

- • कथन 1: सही रेल मंत्रालय, भारत सरकार का एक
- मंत्रालय है जो भारतीय रेलवे के प्रबंधन, संचालन और नियमन के लिए जिम्मेदार होता है।
- • कथन 2: सही - Dedicated Freight Corridors का उद्देश्य है कि मालगाड़ियों और यात्री गाड़ियों को अलग-अलग ट्रैकों पर चलाया जाए ताकि दोनों की गति और दक्षता में वृद्धि हो।
- • कथन 3 गलत- भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई और अहमदाबाद के बीच कार्यान्वित की जा रही है, न कि दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर पर

राज्यपाल और अनुच्छेद 200: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय
Result Mitra

संदर्भ:

- तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की शक्तियों और कर्तव्यों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं।

अनुच्छेद 200 क्या है?

- अनुच्छेद 200 भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल से पारित किसी विधेयक पर निर्णय लेने की शक्ति देता है।

राज्यपाल के विकल्प:

- 1. विधेयक पर सहमति देना
- 2. विधेयक पर सहमति रोकना
- 3. विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना
- 4. गैर-धन विधेयकों को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटाना

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: मुख्य बिंदु

1. 'यथाशीघ्र' का अर्थ – शीघ्र निर्णय लेना अनिवार्य

- राज्यपाल विधेयक को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकता। 'पॉकेट वीटो' (Pocket Veto) या 'पूर्ण वीटो' (Absolute Veto) की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है।

2. पुनः पारित विधेयक पर अनिवार्य स्वीकृति

- यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के बाद वही विधेयक दोबारा पारित किया जाता है (बिना मूलभूत परिवर्तन के), तो राज्यपाल को उस पर अनिवार्य रूप से सहमति देनी होगी।

3. राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य

- राज्यपाल को विधेयक पर निर्णय लेते समय राज्य सरकार की सलाह का पालन करना अनिवार्य है। वे स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते।

4. न्यायपालिका की शक्तियों से संबंधित अपवाद

- यदि कोई विधेयक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करता है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकते हैं।

समय-सीमा का निर्धारण

- सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल को समय-सीमा का पालन करने का निर्देश दिया:
- विधेयकों पर निर्णय लेने में विलंब नहीं होना चाहिए।
- यदि राज्यपाल समय-सीमा का उल्लंघन करते हैं, तो यह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा।

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- 2. राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य होता है।
- 3. राज्यपाल केवल राज्य विधान सभा को भंग करने की शक्ति रखता है, विधान परिषद को नहीं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

व्याख्या:

- कथन 1: सही- अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- कथन 2: सही- अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल सामान्य रूप से मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ संविधान उसे विवेक का उपयोग करने की अनुमति देता है।
- कथन 3: सही - राज्यपाल विधान सभा को भंग कर सकता है, लेकिन विधान परिषद (यदि राज्य में है) को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह एक स्थायी सदन है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) का विलय – चौथा चरण

Result Mitra

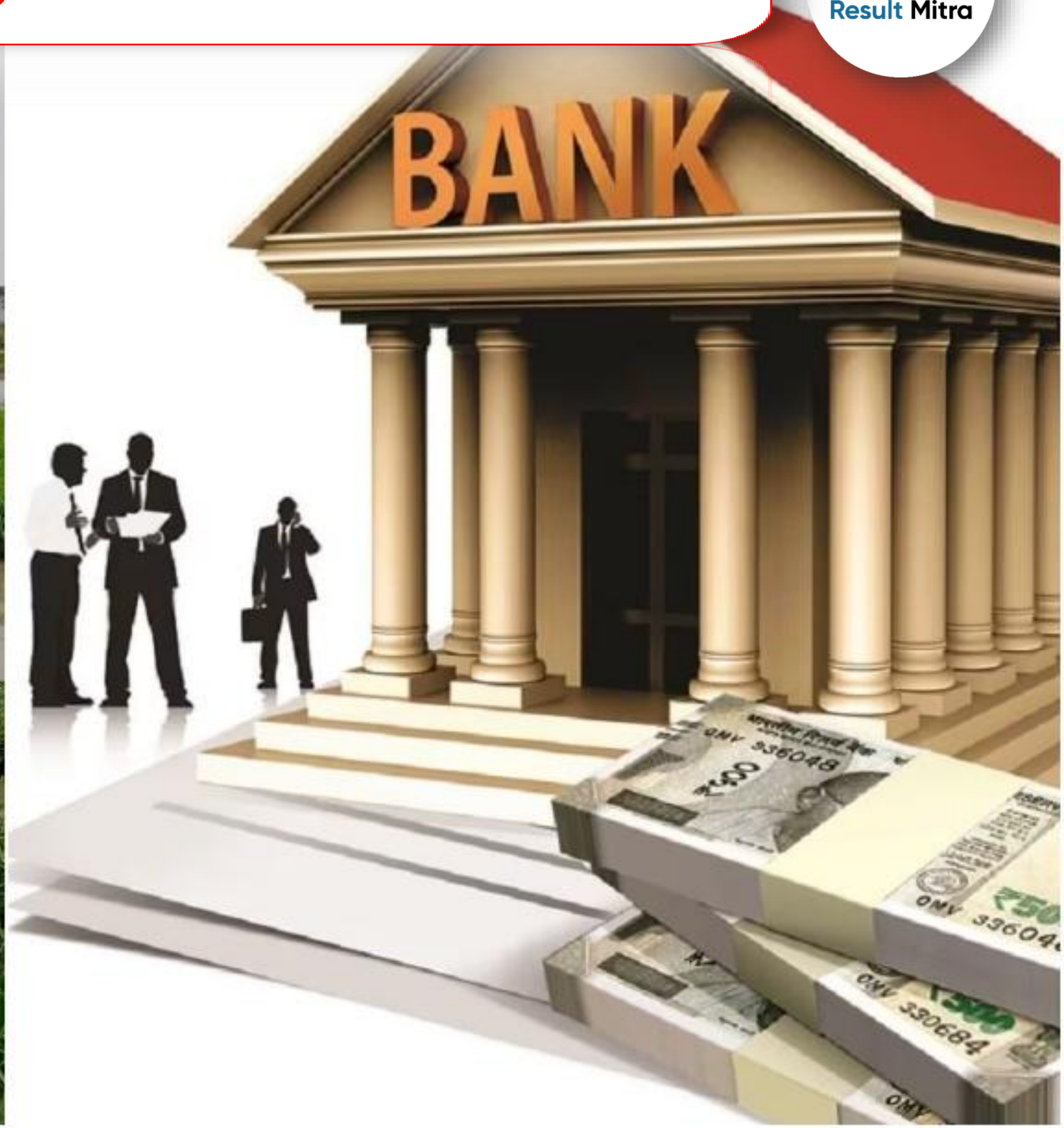

हाल की घोषणा:

- केंद्र सरकार ने देशभर के 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को मिलाकर "एक राज्य, एक RRB" नीति के तहत एक बड़ा फैसला लिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत और सरल बनाना है।

विलय की पृष्ठभूमि:

शुरुआत कब हुई?

- वर्ष 2004-05 में व्यास समिति की सिफारिशों के बाद सरकार ने RRBs का विलय शुरू किया था।

पहले क्या स्थिति थी?

- पहले देश में 196 RRBs थे, जो धीरे-धीरे घटकर 2020-21 तक 43 रह गए।

अब क्या हो रहा है?

- चौथे चरण में 26 बैंकों को मिलाया जा रहा है ताकि हर राज्य में केवल एक ही RRB हो।

विलय का उद्देश्य:

- बैंकिंग सेवाओं को अधिक प्रभावशाली बनाना।
- प्रबंधन और निगरानी को आसान बनाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच बढ़ाना।

"एक राज्य, एक RRB" नीति क्या है?

इस नीति के अनुसार:

- हर राज्य में सिर्फ एक RRB होगा।
- इसका मुख्यालय राज्य के एक प्रमुख शहर में होगा।
- इसे एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख बैंक (जैसे SBI, PNB आदि) प्रायोजित करेगा।

उदाहरण:

- ***बिहार में दो RRBs थे:***

1. दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक

2. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

- इन दोनों को मिलाकर अब एक नया बैंक बना है – बिहार ग्रामीण बैंक, जिसका मुख्यालय पटना में है और प्रायोजक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक।

RRBs क्या हैं?

स्थापना:

- RRBs की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी।
- यह नरसिंहम वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों पर आधारित था।
- बाद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत इन्हें कानूनी रूप से मजबूत किया गया।

उद्देश्य:

- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लघु किसान, मजदूर, कारीगर, और छोटे उद्यमियों को बैंकिंग सुविधाएँ और ऋण प्रदान करना।
- कृषि, छोटे उद्योगों और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।

RRBs का स्वामित्व कैसे बँटा है?

- 50% - केंद्र सरकार
- 15% - राज्य सरकार
- 35% - प्रायोजक बैंक

RRBs पर कौन निगरानी रखता है?

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI): बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत RRBs का नियमन करता है।
- NABARD (नाबार्ड): इन बैंकों की निगरानी और निरीक्षण करता है।

RRBs से जुड़े जरूरी नियम:

1. CRAR (पूंजी पर्याप्तता अनुपात):

- RRBs को 9% CRAR बनाए रखना अनिवार्य है ताकि वे सुरक्षित तरीके से ऋण दे सकें।

2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (PSL):

- RRBs को अपने कुल ऋण का कम से कम 75% प्राथमिकता क्षेत्रों जैसे – कृषि, शिक्षा, छोटे व्यवसाय आदि को देना होता है।

RRBs को कर में क्या छूट है?

- इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के तहत RRBs को सहकारी संस्थाओं का दर्जा प्राप्त है, जिससे उन्हें कुछ कर छूट मिलती है।
- बिलकुल, यहाँ इसी विषय का संक्षिप्त (शॉर्ट) रूप दिया गया है:

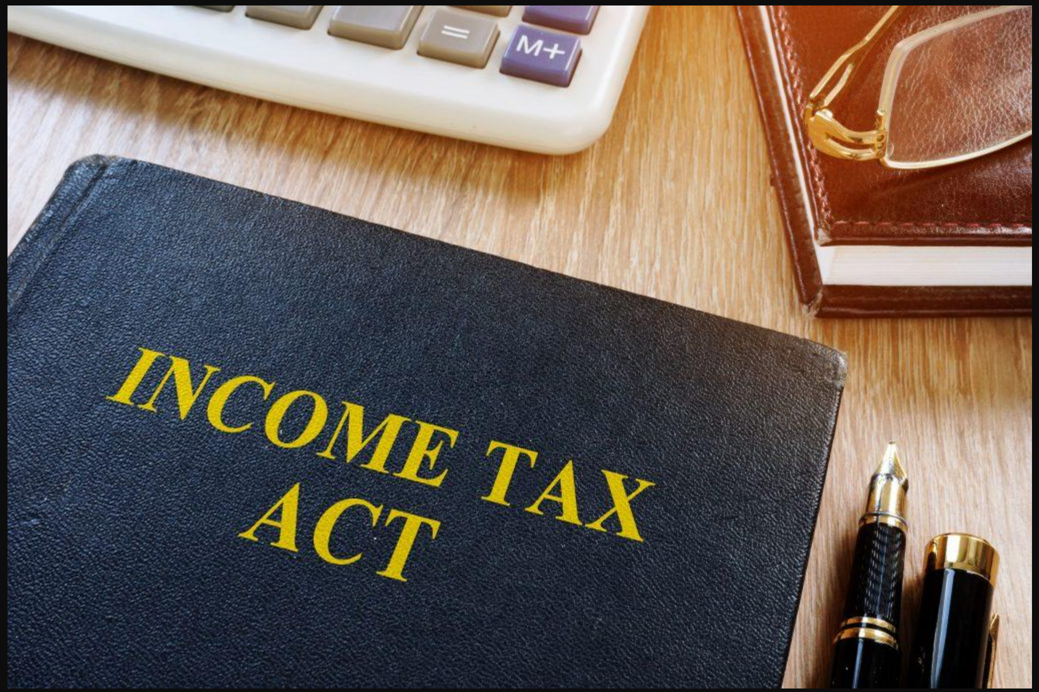

Short notes:–

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) का विलय – संक्षेप में

हाल की घोषणा:

- केंद्र सरकार ने "एक राज्य, एक RRB" नीति के तहत 26 RRBs के विलय की घोषणा की है। यह चौथा चरण है।

पृष्ठभूमि:

- शुरुआत: 2004-05 (व्यास समिति की सिफारिश पर)
- पहले 196 RRBs → अब घटकर 43 (2020-21 तक)
- कानूनी आधार: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976

उद्देश्य:

- बैंकिंग सेवाओं का सुधार
- प्रशासनिक सरलता
- ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवा

Result Mitra

उदाहरण:

- बिहार के दो RRBs का विलय → बिहार ग्रामीण बैंक (मुख्यालय: पटना, प्रायोजक: PNB)

RRBs की मुख्य जानकारी:

- स्थापना: 2 अक्टूबर 1975 (नरसिंहम वर्किंग ग्रुप की सिफारिश पर)
- उद्देश्य: किसानों, मजदूरों, कारीगरों को ऋण व बैंकिंग सुविधा
- स्वामित्व: केंद्र सरकार (50%), राज्य सरकार (15%), प्रायोजक बैंक (35%)

नियमन:

- RBI द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत
- NABARD द्वारा पर्यवेक्षण

महत्वपूर्ण आवश्यकताएं:

- 9% पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR)
- 75% ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना अनिवार्य

कर छूट:

- आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सहकारी संस्था का दर्जा

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है|
- 2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में शेयर होल्डिंग संरचना इस प्रकार होती है: केंद्र सरकार 50% राज्य सरकार - 15%, प्रायोजक बैंक 35%
- 3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्ण स्वामित्व में होते हैं|

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

व्याख्या:

- कथन 1: सही - RRBs की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, खासकर किसानों, छोटे कारोबारियों, कारीगरों आदि के लिए।
- कथन 2: सही - RRBs की शेयरधारिता संरचना केंद्र सरकार (50%), राज्य सरकार (15%) और प्रायोजक बैंक (35%) के बीच होती है।
- कथन 3: गलत - RRBs भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व में नहीं होते, बल्कि उनकी शेयरधारिता ऊपर दिए अनुसार बंटी होती है। RBI इनका विनियामक (regulator) होता है, स्वामी नहीं।

कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) लिमिटेड

हाल की खबर:

- कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 100 लाख गांठ कपास की खरीद की है। यह किसानों को उचित मूल्य दिलाने और बाज़ार में स्थिरता बनाए रखने की एक बड़ी पहल है।

CCI क्या है?

स्थापना:

- 1970 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी।

नोडल मंत्रालय:

- यह संगठन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textiles) के अंतर्गत आता है।

प्रकार:

- यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है।

CCI के मुख्य कार्य:

1. MSP पर कपास की खरीद:

- जब बाज़ार में कपास के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे गिर जाते हैं, तो CCI किसानों से कपास खरीदकर उन्हें नुकसान से बचाता है।

2. कपास की स्टॉकिंग और सप्लाई:

- यह देश के वस्त्र उद्योग को कच्चे माल यानी कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

3. किसानों को समर्थन:

- किसानों को बाजार में बेहतर भाव दिलाने और अनावश्यक बिचौलियों से बचाने का कार्य करता है।

CCI की प्रमुख पहलें:

1. Cott-Ally मोबाइल ऐप:

- यह ऐप 9 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
- किसान इस ऐप से MSP की जानकारी, निकटतम खरीद केंद्र, और अन्य सेवाएं रियल टाइम में प्राप्त कर सकते हैं।

2. QR कोड आधारित ट्रेसिंग सिस्टम:

- CCI द्वारा खरीदी गई हर गांठ कपास पर QR कोड होता है।
- इससे कपास की पूरी जानकारी ट्रैक की जा सकती है – जैसे कहां से खरीदी गई, किस किसान से, किस रेट पर आदि।

क्यों है CCI जरूरी?

- भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक और महत्वपूर्ण निर्यातक देश है।
- किसानों की आय सुनिश्चित करने और वस्त्र उद्योग को नियमित कच्चा माल दिलाने में CCI की भूमिका अहम है।

अतिरिक्त जानकारी:

- भारत में कपास मुख्यत: महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में उगाई जाती है।
- CCI किसानों के साथ मिलकर कपास की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षा कार्यक्रम भी चलाता है।

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद करता है।
- 2. CCI, वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textiles) के अंतर्गत कार्य करता है।
- 3. CCI केवल निर्यात के लिए कपास की खरीद करता है। और घरेलू उपयोग के लिए नहीं ।

उपयुक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

व्याख्या:

- कथन 1 सही CCI की स्थापना 1970 में की गई थी और यह किसानों से कपास की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर करती है, ताकि उन्हें मूल्य में गिरावट से सुरक्षा मिल सके।
- कथन 2: सही - CCI वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textiles), भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है।
- कथन 3: गलत - CCI घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों के लिए कपास की खरीद करता है। इसका उद्देश्य घरेलू कपड़ा उद्योग को स्थिर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना भी है।

Result Mitra